

प्रसारण:— अपराह्न 02:00 बजे से।

अवधि — 05 मिनट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने से देश सुधार की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का विकास राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क और विद्युत प्रणालियों जैसी ठोस संपत्तियों को तैयार करके ही संभव है। श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्रीय बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए बारह लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गयी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक नीतिगत रूपरेखा है। इसलिए, बजट की प्रभावशीलता का आकलन ठोस और महत्वपूर्ण मापदंडों पर किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि जब उद्योग, शिक्षा जगत, विश्लेषक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर सोचते हैं, तो योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होता है और सटीक परिणाम मिलते हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हैं। पूर्णिया में सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री शाह ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प दोहराया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीमांचल के सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुये स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर भी बल दिया। बैठक में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रमुख, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे।

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय ने एन.सी.ई.आर.टी. को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुस्तक में इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना अध्याय जोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई ग्यारह मार्च को होगी।

---

ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत पांच हजार से अधिक आवास कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान के लिए बयालीस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। योजना के क्रियान्वयन से जुड़े संविदा कर्मियों का मानदेय अगस्त दो हजार पच्चीस से लंबित था।

---

दरभंगा जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना के दो आरोपियों को ब्रहमपुर गांव से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

---

किशनगंज जिले के कोचाधामन क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर में ट्रक ड्राइवर और खलासी की मौत हो गयी। वहीं, दूसरे ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

---

लखीसराय के जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-तीस के बच्चों के बीच जीविका के सहयोग से तैयार पोशाक का वितरण किया।

---

सुपौल शहर के लोहिया नगर चौक पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध कब्जे को मुक्त कराया।

---

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।